BCCI BULLETIN

Vol. 55 | February 2024 | No. 02

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

'प्रभात खबर संवाद' में अंतरिम बजट पर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के सदस्यों ने की चर्चा

केन्द्रीय बजट : थोड़ी उम्मीदें, थोड़ी निराशा

केन्द्रीय अंतरिम बजट 2024-2025 का लाइव प्रसारण देखते चैम्बर के पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण।

केन्द्रीय वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2024 को छठा बजट पेश किया। इसे लेकर बिहार चैम्बर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इडस्ट्रीज में 'प्रभात खबर संवाद' के तहत 'केन्द्रीय अंतरिम बजट 2024-25' पर संवाद आयोजित की गयी। इसमें शहर के नामी-गिरामी कारोबारी मौजूद रहे। बजट को लेकर चैम्बर की ओर से सभा कक्ष में प्रोजेक्टर लगाया गया था। बजट पेश होने से पहले सदस्यों को वित्त मंत्री से कुछ विशेष एलान की उम्मीद थी, पर ऐसा कुछ नहीं मिला। हालांकि, सदस्यों ने कहा कि आज का बजट एक अंतरिम बजट है, यह व्यापक और अभिनव है। ओवर ऑल इस बजट से जहाँ अधिकांश सदस्य खुश दिखे, वहीं कई सदस्य थोड़े दुखी भी नजर आये।

उद्यम वर्ग को मिल सकती है राहत

"बजट 2047 में विकसित भारत की नींव रखने की गारंटी देता है। बजट में आयकर छूट योजना का ऐलान इस योजना से एक करोड़ मध्यम वर्ग के लोगों को राहत मिलेगी। बजट सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए सहायक है। बजट में किसानों के लिए बड़े फैसले लिए गये हैं। इनमें नैनो डीएपी का उपयोग, पीएम मातृ संपदा योजना का विस्तार आदि शामिल है। इन योजनाओं से न सिर्फ किसानों की आय बढेगी बल्कि खर्च भी कम होगा।"

– पी. के. अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष

निवेश बढ़ाने का प्रस्ताव प्रशंसनीय

"आज का बजट एक अंतरिम बजट है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किसी प्रकार का परिवर्त्तन नहीं किया जाना, पर्यटन के विकास के लिये धन उपलब्ध कराना, पीएम गति शक्ति के तहत तीन प्रमुख आर्थिक रेलवे गलियारे की घोषणा के साथ स्टार्टअप के लिये टैक्स छूट की अवधि का विस्तार, सनराइज टेक्नोलॉजी एवं रिन्यूबल इनर्जी में निवेश को बढ़ावा देने का प्रस्ताव जैसी घोषणा काफी प्रंशसनीय है।"

– आशीष शंकर, उपाध्यक्ष

बजट में इस बार कुछ खास नहीं रहा

"सरकार के इस अंतरिम बजट में 75,000 करोड़ रुपये की लागत से विकसित भारत के लिए राज्य-स्तर पर भी मजबूत फोकस है। बजट में स्टार्टअप को टैक्स छूट को एक साल के लिए विस्तार दिया गया है, जो अच्छा कदम है। अंतरिम बजट होने के कारण बजट में कुछ खास नहीं रहा। टैक्स में बदलाव को लेकर लोगों को उम्मीद थी, उस पर पानी फिर गया। हालांकि स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट एक साल के लिए बढ़ाई गयी है, यह अच्छी बात है।"

– प्रदीप चौरसिया, उपाध्यक्ष

विकासोन्मुख है केन्द्रीय अंतरिम बजट

"मिडिल क्लास के लिए हाउसिंग स्कीम लायेगी, जिससे सरकार अगले पाँच साल में दो करोड़ घर बनायेगी। बजट विकासोन्मुख है। सरकारी पूंजी व्यय पर शत-प्रतिशत वृद्धि से रोजगार का सृजन होगा। साथ ही बजट में शिक्षा के लिए बेहतर साबित होगा। क्योंकि अब निजी से लेकर सरकारी स्कूलों को डिजिटल किया जायेगा। हालांकि यह अंतरिम बजट है। मई में लोकसभा चुनाव के बाद जो नयी सरकार आएगी वह आम बजट पेश करेगी।"

– सुबोध जैन, कोषाध्यक्ष

रोजगार के नये अवसर पैदा होंगे

"इस बजट में दो अहम फैसले लिये गये हैं। शोध पर एक लाख करोड़ रुपये का फंड बनाने का ऐलान किया गया है। स्टार्टअप्स के लिए उपलब्ध टैक्स छूट का विस्तार करने की भी घोषणा की गयी है। यह बजट विकसित भारत के

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं,

जनवरी 2024 में जीएसटी संग्रह 1.70 लाख करोड़ का रहा जो दूसरा सबसे अधिक संग्रह है यानि जीएसटी संग्रह में 10.4 प्रतिशत की ग्रोथ दर्ज की गई है । देश की अर्थ व्यवस्था में जीएसटी का योगदान काफी अच्छा है ।

माननीया केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 47.66 लाख करोड़ का अंतरिम बजट 2024–25 लोक सभा में दिनांक 1 फरवरी, 2024 को पेश किया । इस अंतरिम बजट में दीर्घकालिक विकास पर जोर दिया गया है । देश में तीन नये रेल कॉरिडोर का निर्माण, मालगाड़ी गलियारा निर्माण, रेलवे की साधारण बोगियों को बंदे भारत जैसी बोगियों में परिवर्त्तन तथा बड़े व छोटे शहरों में नये मेट्रो का विस्तार का प्रावधान सराहनीय है । इलेक्ट्रीक वाहनों को बढ़ावा देना, स्टार्टअप के लिए कर में छूट की अवधि का विस्तार जैसी घोषणा स्वागत योग्य है । अंतरिम बजट में सर्व समावेशी विकास पर बल देते हुए सभी को सशक्त बनाने का प्रयास किया गया है । लोग आशान्वित थे कि इस बजट में करों में कुछ छूट देने के साथ ही आयकर स्लेब को बढ़ाया जायेगा । वैसे भी यह एक अंतरिम बजट है जो केन्द्र सरकार कुछ महीनों के अपने खर्चे के लिए पेश करती है । इसलिए हमें बहुत उम्मीद भी नहीं थी । इस बजट में रेल परियोजनाओं हेतु 10,032 करोड़ मिले हैं, पं0 दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन से मेन लाईन समेत तीन रेल लाईन 4 ट्रेक वाली होगी । बिहार को जल्द ही बंदे भारत एवं अमृत भारत ट्रेनें मिलेंगी ।

माननीय वित्त वाणिज्य कर मंत्री श्री सम्राट चौधरी ने दिनांक 13 फरवरी, 2024 को 2.78 लाख करोड़ का बिहार बजट 2024–25 पेश किया । इस बजट से कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना प्रावेधिकी, पर्यटन उद्योग और निवेश को बढ़ावा मिलेगा । साथ ही बजट में पर्यटन एवं कृषि क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया है । इससे राज्य के आर्थिक विकास में अनुकूल प्रभाव पड़ेगा । वहीं आई टी क्षेत्र में बढ़ावा देने से राज्य में रोजगार सृजन होगा । बजट में उद्योग के लिए 1833 करोड़ 9 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है ।

इस बजट में इलेक्ट्रीक वाहनों में छूट एवं सौर उर्जा में प्रोन्नति से प्रदूषण को काफी हद तक कम करने में सहायक होगा। कुल मिलाकर बिहार बजट सराहनीय है एवं राज्य के चहुँमुखी विकास में सहायक होगा।

अंतरिम बजट के ठीक बाद भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अल्पकालिक ऋण दर (रेपो रेट) पर यथास्थिति जारी रखने की संभावना है। विशेषज्ञों के कथनानुसार सेन्ट्रल बैंक आगामी द्विमासिक मौद्रिक नीति में नीतिगत दरों में कोई बदलाव शायद ही करे, क्योंकि खुदरा मुद्रास्फीति अभी भी संतोषजनक दायरे के उपरी स्तर के करीब है।

2 फरवरी, 2024 को बिहार विद्युत विनियामक आयोग, पटना की बिजली दरों में वृद्धि पर अंतिम जन सुनवाई हुई । इस जन सुनवाई में आमजनों सहित उद्योग व्यापार के प्रतिनिधि उपस्थित हुए । सभी ने एक स्वर में कहा कि बिजली की दरों में किसी भी तरह की वृद्धि नहीं होनी चाहिए । **बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से आयोग से अपील की गयी कि उद्योगों के लिए बिजली की दरों में कमी लायी जाये । परिचम बंगाल, ओडिशा, झारखंड से बिहार की बिजली मंहगी है । ऐसे में बिहार के उद्योग प्रतिस्पर्धा कैसे कर सकेंगे । डिमाण्ड चार्ज में कमी की जाए । पश्चिम बंगाल में कोल्ड स्टोरेज को कृषि के टैरिफ में रखा गया है । बिहार में भी कोल्ड स्टोरेज, हर्टिकल्चर के लिए कृषि टैरिफ के तहत बिजली उपलब्ध करायी जाये । नियम और शर्तो में बदलाव नहीं किया जाये अन्यथा उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा । आयोग डिस्ट्रीब्यूशन लॉस 10 प्रतिशत और ट्रांसमिशन लॉस एक प्रतिशत निर्धारित करें । आयोग ने बिजली वृद्धि पर फैसला सुरक्षित रख लिया है जो फरवरी 2024 के अन्त तक आने की उम्मीद है ।**

बिहार के 12 जिलों में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण होगा और इसका संचालन सौर उर्जा से किया जायेगा । इतना ही नहीं, उद्योग विभाग के तहत पूर्व से निर्मित कोल्ड स्टोरेजों को भी सौर उर्जा से संचालित किया जायेगा । इससे किसानों को फल, सब्जी आदि के भंडारण में सुविधा होगी और खर्च भी कम आएगा । चौथे कृषि रोड मैप के तहत बागवानी विकास कार्यक्रम के तहत राज्य स्कीम मद से यह कार्य किये जायेंगे । 12 जिलों में नये कोल्ड स्टोरेज के निर्माण पर 50 फीसद की सहायता अनुदान भी दिया जायेगा । इस योजना के तहत पहले आओ पहले पाओं के तर्ज पर लाभ दिया जायेगा । इसके लिए ऑन लाईन आवेदन करना होगा । राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत कोल्ड स्टोरेज को सौर उर्जा से संचालित करने के लिए अधिकतम 35 लाख का 50 प्रतिशत अर्थात् 17.50 लाख अनुदान दिया जायेगा । नये कोल्ड स्टोरेज निर्माण जिन 12 जिलों में होने हैं, वे जिले हैं – मधुबनी, शिवहर, नवादा, औरंगाबाद, बांका, सहरसा, जमुई, मुंगेर, जहानाबाद, लखीसराय, शेखपुरा एवं अरवल ।

इन कोल्ड स्टोरेज के निर्माण होने से उन जिलों के किसानों को काफी सुविधा रहेगी । चैम्बर भी कई अवसरों पर कोल्ड स्टोरेज के निर्माण और अनुदान का आग्रह सरकार से करता रहा है ।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने जय प्रभा मेदान्ता के सहयोग से दिनांक 10 फरवरी 2024 को चैम्बर प्रांगण में हेल्थ चेकअप कैम्प लगाया था । इस कैम्प में काफी लोगों के स्वास्थ्य की जॉच की गयी और उचित परामर्श भी दिया गया । कैम्प से सम्बन्धित रिपोर्ट इसी बुलेटिन में प्रकाशित।

होली की हार्दिक शुभकामनाएँ ।

सादर,

आपका

सुभाष पटवारी

चार स्तंभों युवा, गरीब, महिला और किसान को सशक्त करेगा। आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के साथ-साथ युवाओं के लिए रोजगार के नये अवसर पैदा होंगे।" **– पशुपति नाथ पाण्डेय, महामंत्री**

मजबूत भारत का दिखा संकल्प

"चूँकि इस बार का बजट अंतरिम बजट था, इसलिए इस बजट से बहुत उम्मीदें नहीं थी। हालांकि मध्यम वर्ग और नौकरी-पेशा लोगों को आयकर में कुछ राहत मिलने की उम्मीदें थी, उन्हें थोड़ी निराशा जरूर हुई होगी। पर यह अंतरिम बजट सरकार की नीतियों और स्कीम के दृष्टिकोण को रेखांकित करता है जिसमें इंक्लूसिव एंड सस्टेंड ग्रोथ की बात कहीं गई है जो एक मजबूत और विकसित भारत बनाने का सकल्प दर्शाता है।" **– सुनील सराफ, सदस्य**

आम आदमी को साधने की कोशिश

"सरकार ने जनहित में कई कदम उठाये हैं। इस बजट में सबसे अहम बात महिलाओं के लिए की गयी कई घोषणाएँ हैं। इसके अलावा भी अलग-अलग सेक्टर्स को लेकर कई योजनाओं का एलान किया गया है। सरकार ने इस बजट में आम आदमी को साधने की पूरी कोशिश की। महिलाओं के लिए कई काम हुए। सौर प्रणाली वाले एक करोड़ परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली की बातें भी कही गयी है।" **– अजय कुमार गुप्ता, सदस्य**

बजट में बढ़ता भारत दिखता है

"बजट में वित्त मंत्री ने पिछले 10 वर्षों में सरकार की उपलब्धि को दर्शाया है। कौशल क्षेत्र के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धिं 14 करोड़ युवाओं की मदद करने के लिए पहल की है। आइआइटी, आइआइएम, एम्स सेटअप अच्छी उपलब्धि है। बजट में डिजिटल उपकरण को विकसित करने में मदद करने पर बल दिया गया है। कुछ मिलाकर अंतरिम बजट में बढ़ता भारत दिखता है। देश बढ़ेगा तब हम सब बढ़ेंगे।" **– मुकेश सिन्हा, सदस्य**

यह बजट राहत देने वाला

"यह एक अंतरिम बजट है जिसमें सरकार ने युवा शक्ति को बढ़ाने के लिए स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने की बात कही गयी है। इससे रोजगार की संभावनाएँ बढ़ेगी और राष्ट्र का विकास और आत्मनिर्भर भारत की ओर से देश तेजी से अग्रसर होंगे। सरकार ने सभी के प्रयास की वकालत की है। बढ़ती बेरोजगारी के बीच ये बजट युवाओं को राहत देने वाला है। इस बजट में पीएम से शुरू होने वाली योजनाएँ खूब सारी गिनायी गयी।" **– आशीष प्रसाद, सदस्य**

रेलवे यातायात होगा सुगम

"बजट में अमृतकाल में प्रधानमंत्री गति-शक्ति योजना के तहत तीन महत्वपूर्ण रेलवे मॉल परिवहन कोरिडोर जो उर्जा, सीमेंट एवं खनिज कोरिडोर, पत्तन कोरिडोर तथा अधिक दबाब वाले रेलवे यातायात को सुगम बनाने के लिए कोरिडोर, जिस पर सरकार 2.55 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी। इससे निश्चित तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के साथ-साथ लाखों रोजगार का सृजन होगा। 40 हजार रेलवे की बोगियों को वंदे भारत केटेगरी का बनाया जायेगा।"

– सुधी रंजन, सदस्य

आयकर स्लैब को बढ़ाना चाहिए था

"बजट में समावेशी विकास को प्राथमिकता दी गयी है। बजट में की गयी घोषणा व्यापार की सुगमता में सुधार लायेगी। हालांकि ऐसी आशा की जा रही थी कि करों में कुछ छूट दी जायेगी तथा आयकर स्लैब को बढ़ाया जायेगा। बजट न केवल बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास में बल्कि सशक्तिकरण में भी योगदान देगा। मिडिल क्लास को घर देने की घोषणा का स्वागत किया जाये, कम होगा।" **– पवन कुमार भगत, सदस्य**

महिलाओं के लिए उम्मीद से कम घोषणा

"अगले पाँच दशकों के लिए राज्यों को कुल 75 हजार करोड़ रुपये का ब्याज-मुक्त ऋण प्रदान करने का निर्णय केन्द्र-राज्य संबंधों को मजबूत करने में गेंम चेंजर साबित होगा। साथ ही लॉजिस्टिक कार्यकुशलता व लागत को कम करने के लिए पीएम गति शक्ति के तहत तीन बड़े रेलवे कॉरिडोर की घोषणा भविष्य के लिए अच्छा है। महिलाओं के लिए उम्मीद से कम घोषणाएँ हुई हैं।"

– मुकेश जैन, सदस्य

निरंतरता और विश्वास का बजट है

"बजट दूरदर्शी है और यह निरंतरता और विश्वास का बजट है। एक एकीकृत तथा न्यायसंगत विकास बजट परिव्यय को 'डिकोड' किया है जिसमें सामाजिक सुधार, आर्थिक वृद्धि मूल्य श्रृंखला को बढ़ाना, उभरते क्षेत्रों पर जोर देना और शहरी और ग्रामीण आवास को प्रोत्साहन देना शामिल है। बजट में आर्थिक वृद्धि के लिए एक व्यापक मार्ग प्रशस्त किया है जो भारत को 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल करने में सक्षम बनायेगा।"

– नमित पटवारी, सदस्य

करों से संबंधित कोई बदलाव नहीं

सरकार द्वारा 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए मुख्य रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े निवेश की घोषणा की गयी है। साथ ही युवाओं महिलाओं और छोटे उद्यमियों के सशक्तिकरण के लिए कई योजनाओं की रूप रेखा रखी गयी है।" **– राजेश कुमार खेतान, सदस्य**

एक्साइज ड्यूटी में फेरबदल नहीं

"सरकार ने इस बजट में टैक्सेशन रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। इससे आम लोगों को राहत मिलेगी। सरकार ने छोटी कीमत की विवादित आयकर मांग को बट्टे खाते में डालने की घोषणा की है जो एक स्वागत योग्य कदम है, गोल्ड को लेकर एक्साइज ड्यूटी में कोई अधिक फेरबदल नहीं हुआ है। बजट में हरित विकास और समावेशी विकास पर भी जोर दिया गया है।"

– आशीष अग्रवाल, सदस्य

गरीब, महिला और किसान पर फोकस

"सरकार से इस बजट में ज्वेलरी सेक्टर को कोई बड़ी अपेक्षा नहीं थी, यह अतरिम बजट गरीब, युवा, महिला और किसान को फोकस कर पेश किया गया। सरकार ने पिछले 10 वर्षों में बजट के जरिये अपनी उपलब्धियों का जिक्र किया है। वित्त मंत्री ने डायरेक्ट और इनडाइरेक्ट दोनों टैक्स संग्रह में बढ़ोतरी का जिक्र किया है। अत: आने वाली सरकार द्वारा पेश होने वाले बजट में अच्छी राहत की उम्मीदें बरकरार है।"

– विनोद कुमार, अध्यक्ष, पाटलीपुत्रा सराफा संघ

देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनेगा

"इस बजट में मुख्य रूप से दस सालों में विकास के लिए काम करने पर बल दिया गया है। खासकर स्वास्थ्य आर्थिक और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में फोकस किया गया है। सरकार अगले 25 सालों के विजन को लेकर चल रही है। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्वस्तरीय बनाने के लिए जहाँ बजट में एक तरफ 11.1 फीसदी बढोतरी कर इसे रिकाई 11.11 लाख करोड़ रुपये किया है।"

– अरुण कुमार, सदस्य

बाजार में पैसे की गतिशीलता बढ़ेगी

"वित्त मंत्री की और से जो बजट पेश किया गया, उसमें सीधे तौर पर व्यापारियों को कोई लाभ नहीं दिखता है, लेकिन इंफ्राटक्चंर में काफी प्रोत्साहन दिख रहा है। इसका सीधा लाभ कारोबारियों को मिलेगा।"

– अजय कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष, बिहार इलेक्ट्रिक ट्रेडर्स एसोसिएशन

देश के विकास के लिए है बजट

"आयकर की सीमा में कोई बदलाव नहीं किए जाने का फायदा बिहार समेत देश के लोगों को मिलेगा। केन्द्रीय बजट के आधार पर ऐसा लग रहा है कि उपभोक्ता वस्तुओं के दाम में बढोतरी नहीं होगी। यह देश के विकास के पेश किया गया बजट है।"

– किशोर कुमार अग्रवाल, समन्वयक, आरटीआइ सेल, बिहार चैम्बर

टैक्स को ले सरकार का अच्छा प्रयास

आज का बजट काफी फ्लैट है। गोल्ड को लेकर एक्साईज इयूटी में कोई ज्यादा फेरबदल नहीं हुआ है। बजट में सराफा कारोबारियों को सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। टैक्स को लेकर सरकार का अच्छा प्रयास है। ओवरऑल बेहतर बजट है।" **- शशि कुमार**

महासचिव, पाटलिपुत्र सराफा संघ

(साभार : प्रभात खबर, 2.2.2024)

जयप्रभा मेदान्ता हॉस्पिटल के सहयोग से चैम्बर प्रांगण में चेक अप कैम्प आयोजित

दीप प्रज्वलित कर चेकअप कैम्प का उद्घाटन करते जयप्रभा मेदान्ता के मेडिकल डायरेक्टर डॉ. रवि शंकर सिंह, चैम्बर के पदाधिकारीगण, पूर्व अध्यक्ष, कार्यकारिणी सैदस्यगण एवं मेदान्ता के चिकित्सकगण।

मरीजों की जाँच करते मेदान्ता के चिकित्सकगण

मरीज की इको जाँच करतीं मेदांता की एक्सपर्ट टेक्नीशियन

कैंप में मरीज की इसीजी की जाँच करते मेदान्ता के टेक्नीशियन

ब्लड सूगर एवं बी.पी. की जाँच कराते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से जय प्रभा मेदान्ता मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सहयोग से दिनांक 10 फरवरी 2024 को चेक अप कैम्प का आयोजन चैम्बर प्रांगण में किया गया जिसमे काफी संख्या में सदस्यों, उनके परिजनों सहित आम लोगों ने भी अपना-अपना चेक अप कराया। कैम्प का उदघाटन मेदान्ता के मेडिकल डायरेक्टर डॉ. रवि शंकर सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया।

चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी ने बताया कि आज के चेकअप कैम्प में जयप्रभा मेदान्ता हॉस्पिटल के डॉ. पवन कुमार सिंह, कार्डियोलोजिस्ट, डॉ. मुकुंद प्रसाद, न्यूरोलोजिस्ट, डॉ. मृत्युंजय कुमार, इन्टरनल मेडिसिन, डॉ. कर्नल संतोष कुमार, ओर्थोपेडिक्स एवं डॉ. नाजिया मजीद, क्लिनिकल एसोसिएट के द्वारा रोगों की जाँच कर परामर्श दिया गया। उन्होंने आगे बताया कि कैम्प में ईको, ई.सी.जी., शुगर, बी.पी. की भी जाँच की गयी।

श्री पटवारी ने बताया कि चैम्बर न केवल राज्य के व्यावसायिक हित के कार्यों बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्वों के कार्यों यथा – बाढ़, सुखाड़, प्राकृतिक आपदाओं में आर्थिक सहयोग के साथ-साथ समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कौशल विकास जैसे कार्यों के निर्वहन में सदैव आगे बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेता रहा है। इसी क्रम में आज मेदान्ता हॉस्पिटल के सहयोग से चैम्बर प्रांगण में चेकअप कैम्प का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य पटना के वैसे लोग जो बड़े-बड़े शहरों में स्थित अस्पतालों में जाकर अपना चेकअप कराने में असमर्थ होते हैं उन्हें पटना में ही बेहतर चेकअप एवं डॉक्टर का परामर्श प्रदान

डॉ. रवि शंकर सिंह, मेडिकल डायरेक्टर मेदांता को बूके, शॉल एवं मेमेन्टो भेंटकर सम्मानित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल एवं उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर।

मेदान्ता के डॉ. कर्नल संतोष कुमार, हड्डी रोग के विशेषज्ञ को बूके, मेमेन्टो, शॉल एवं बुलेटीन भेंटकर सम्मानित करते चैम्बर पदाधिकारीगण, पूर्व पदाधिकारीगण एवं कार्यकारिणी के सदस्यगण

मेदांन्ता के हृदयरोग निशेषज्ञ डॉ. पवन कुमार सिंह को पुष्प, शॉल, मेमेन्टो एवं बुलेटीन भेंटकर सम्मानित करते चैम्बर के पदाधिकारीगण, पूर्व पदाधिकारीगण एवं कार्यकारिणी के सदस्यगण

मेदांता के डॉ. मृत्यंजय कुमार को पुष्प, शॉल, मेमेन्टो एवं बुलेटीन भेंटकर सम्मानित करते चैम्बर के पदाधिकारीगण, पूर्व पदाधिकारीगण एवं कार्यकारिणी के सदस्यगण

कराना है। इसके पूर्व भी चैम्बर कि ओर से अन्य हेल्थ चेकअप कैम्पों के साथ -साथ मेदान्ता के सहयोग से इस प्रकार का कैम्प माह जनवरी 2017, दिसम्बर 2017 एवं दिसम्बर 2021 में किया गया था।

चेकअप कैम्प के सफल संचालन में चैम्बर की ओर से उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर एवं श्री प्रदीप चौरसिया, कोषाध्यक्ष श्री सुबोध जैन, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, पूर्व उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं श्री एन. के. ठाकुर, कार्यकारणी सदस्य श्री पवन भगत, श्री सावल राम ड्रोलिया, श्री अजय कुमार, श्री रवि गुप्ता, श्री बहजाद करीम, श्री अशोक कुमार, श्री राकेश कुमार, श्री बिनोद कुमार, श्री आलोक पोद्दार ने अपना योगदान किया।

चैम्बर की ओर से सभी डॉक्टरों एवं टेक्निशियनों को पुष्प, शॉल, चैम्बर का मेमेंटो एवं बुलेटिन भेंटकर सम्मानित किया गया।

मेदान्ता की क्लिनिकल एसोसियेट डॉ. नाजिया मजीद को पुष्प, शॉल, मेमेन्टो एवं बुलेटीन भेंटकर सम्मानित करते चैम्बर के पदाधिकारीगण, पूर्व पदाधिकारीगण एवं कार्यकारिणी के सदस्यगण

अंतरिम बजट 2024-25 की मुख्य बातें

वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' के मंत्र और 'सबका प्रयास' के संपूर्ण राष्ट्र के दृष्टिकोण के साथ संसद में दिनांक 01 फरवरी, 2024 को अंतरिम बजट 2024-25 पेश किया। इस बजट की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

भाग- क

सामाजिक न्याय : • चार प्रमुख वर्गों यानी गरीब, महिलाएँ, युवा एवं अन्नदाता (किसान) को ऊपर उठाने पर प्रधानमंत्री का फोकस।

'गरीब कल्याण, देश का कल्याण' : • पिछले 10 वर्षों के दौरान सरकार ने 25 करोड़ लोगो को बहुआयामी गरीबी से बाहर आने में मदद की • पीएम-जनधन खातों के उपयोग से बैंक खातों में 34 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष हस्तांतरण। इससे सरकार को 2.7 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई • पीएम-स्वनिधि के तहत 78 लाख फेरी वालों को ऋण सहायता। 2.3 लाख फेरी वालों को तीसरी बार ऋण प्राप्त हुआ • पीएम-जनमन योजना के जरिए विशेष तौर पर कमजोर आदिवासी समूहों (पीवीटीजी) के विकास पर जोर • पीएम-विश्वकर्मा योजना के तहत 18 व्यवसायों से जुड़े कारीगरों एवं शिल्पकारों को एण्ड-टू-एण्ड मदद।

'अन्नदाता' का कल्याण : • पीएम-किसान सम्मान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई • पीएम-फसल बीमा योजना के तहत चार करोड़ किसानों को फसल बीमा उपलब्ध कराई गई • इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्किट (ई-नाम) के तहत 1,361 मंडियों को

चैम्बर का प्रतिनिधिमंडल
नव पदस्थापित प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (बिहार-झारखंड) से मिला

नव पदस्थापित प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (बिहार-झारखण्ड) श्री मनोरंजन पाणिग्रही को पुष्पगुच्छ भेंटकर अभिनन्दन करते चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। साथ में प्रतिनिधिमंडल के सदस्यगण।

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (बिहार-झारखण्ड) श्री मनोरंजन पाणिग्रही से विचार-विमर्श करते चैम्बर प्रतिनिधिमंडल के सदस्यगण।

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (बिहार-झारखण्ड) श्री मनोरंजन पाणिग्रही से विचार-विमर्श करते चैम्बर प्रतिनिधिमंडल के सदस्यगण।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज का एक प्रतिनिधिमंडल चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी के नेतृत्व में दिनांक 8 फरवरी, 2024 को नव पदस्थापित प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (बिहार-झाखंड) श्री मनोरंजन पाणिग्रही से मिला और आयकर संबंधी विषयों पर विचार-विमर्श किया। इस प्रतिनिधिमंडल में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर एवं श्री प्रदीप चौरसिया, कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन, महामंत्री पशुपति नाथ पायडेय, पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, पूर्व उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, कार्यकारिणी सदस्य श्री सुनील सराफ, श्री आशीष अग्रवाल एवं श्री अंजन विश्वास शामिल थे।

एकीकृत किया गया है। इससे 3 लाख करोड़ रुपए की खरीद-फरोख्त के साथ 1.8 करोड़ किसानों को सेवाएँ उपलब्ध।

नारी शक्ति पर जोर : • 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए • उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन 28 प्रतिशत तक बढ़ा • स्टेम पाठ्यक्रमों में छात्राओं एवं महिलाओं का 43 प्रतिशत नामांकन, जो दुनिया में सबसे अधिक है • पीएम-आवास योजना के तहत 70 प्रतिशत मकान ग्रामीण महिलाओं को दिए गए।

पीएम आवास योजना (ग्रामीण) : • कोविड संबंधी चुनौतियों के बावजूद पीएम-आवास योजना (ग्रामीण) के तहत तीन करोड़ मकानों का लक्ष्य जल्द ही हासिल किया जाएगा • अगले पाँच वर्षों में 2 करोड़ अतिरिक्त मकानों का लक्ष्य लिया जाएगा।

छत पर सौर प्रणाली लगाना (रूफटॉप सोलराइजेशन) और निशुल्क बिजली : • छत पर सौर प्रणाली लगाने से 1 करोड़ परिवार हर महीने 300 यूनिट तक निशुल्क बिजली प्राप्त कर सकेंगे • हरेक परिवार को सालाना 15,000 से 18,000 रुपए की बचत होने का अनुमान।

आयुष्मान भारत : • आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य सेवा सुरक्षा में सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को भी शमिल किया जाएगा।

कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण : • प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना से 38 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं और रोजगार के 10 लाख अवसरों का सृजन हुआ है • प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम के औपचारिकीकरण योजना से 2.4 लाख स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) और 60,000 लोगों को ऋण सुविधा प्राप्त करने में मदद मिली है।

आर्थिक उन्नति रोजगार और विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान एवं नवाचार : • 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के साथ एक लाख करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया जाएगा। इस कोष से दीर्घकालिक वित्त पोषण या पुनर्वित्तपोषण कम या शून्य ब्याज दरों पर उपलब्ध कराए जाएँगे • रक्षा उद्देश्यों के लिए डीप-टेक प्रौद्योगिकी को मजबूती देने और आत्म निर्भरता में तेजी लाने के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी।

बुनियादी ढांचा : • बुनियादी ढांचा के विकास और रोजगार सृजन के लिए पूंजीगत व्यय के परिव्यय को 11.1% बढ़ाकर 11.11, 111 करोड़ रुपए किया जा रहा है। यह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.4% होगी।

चैम्बर का प्रतिनिधिमंडल आयकर महानिदेशक (अन्वेषण) (बिहार, झारखंड) से मिला

आयकर महानिदेशक (अन्वेषण) (बिहार-झारखण्ड) श्री राहुल कर्ण को पुष्पगुच्छ भेंटकर अभिनन्दन करते चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। साथ में प्रतिनिधिमंडल के सदस्यगण

आयकर महानिदेशक (अन्वेषण) (बिहार-झारखण्ड) श्री राहुल कर्ण से विचार-विमर्श करते चैम्बर प्रतिनिधिमंडल के सदस्यगण

आयकर महानिदेशक (अन्वेषण) (बिहार-झारखण्ड) श्री राहुल कर्ण से विचार-विमर्श करते चैम्बर प्रतिनिधिमंडल के सदस्यगण

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज का एक प्रतिनिधिमंडल चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी के नेतृत्व में दिनांक 8 फरवरी, 2024 को आयकर महानिदेशक (अन्वेषण) (बिहार-झाखंड) श्री राहुल कर्ण से मिला और आयकर संबंधी विषयों पर विचार-विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर एवं श्री प्रदीप चौरसिया, कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन, महामंत्री पशुपति नाथ पायडेय, पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, पूर्व उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, कार्यकारिणी सदस्य श्री सुनील सराफ, श्री आशीष अग्रवाल एवं श्री अंजन विश्वास शामिल थे।

रेलवे : • लॉजिस्टिक्स कुशलता को बेहतर करने और लागत घटाने के लिए पीएम गतिशक्ति के तहत तीन प्रमुख आर्थिक रेल गलियारा कार्यक्रमों की पहचान की गई है • ऊर्जा, खनिज एवं सीमेंट गलियारा • पत्तन संपर्कता गलियारा • अधिक यातायात वाले गलियारा • 40, 000 सामान्य रेल डिब्बों को 'वंदे भारत' मानकों के अनुरूप बदला जाएगा।

विमान्न क्षेत्र : • देश में हवाई अड्डों की संख्या 149 पर हुई दोगुनी • 517 नए हवाई मार्ग 1.3 करोड़ यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुँचा रहे हैं • देश की विमानन कंपनियों ने 1,000 से अधिक नए विमानों के लिए ऑर्डर दिए।

हरित ऊर्जा : • वर्ष 2030 तक 100 मीट्रिक टन की कोयला गैसीकरण और तरलीकरण क्षमता स्थापित की जाएगी • परिवहन के लिए कम्प्रस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) और घरेलू प्रयोजनों के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) में कम्प्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) के चरणबद्ध अधिदेशात्मक मिश्रण को अनिवार्य किया जाएगा।

पर्यटन क्षेत्र : • राज्यों को प्रतिष्ठित पर्यटक केन्द्रों का संपूर्ण विकास शुरू करने, उनकी वैश्विक पैमाने पर ब्रांडिंग और मर्केटिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा • पर्यटन केन्द्रों को वहाँ उपलब्ध सुविधाओं और सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर रेटिंग देने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा • इस प्रकार की गतिविधियों का वित्त पोषण करने के लिए राज्यों को मैचिंग के आधार पर ब्याज मुक्त दीर्घावधि ऋण दिया जाएगा।

निवेश : • वर्ष 2014 से 2023 के दौरान एफडीआई का अंतर्प्रवाह 596 अरब डॉलर रहा, जो वर्ष 2005 से 2014 के दौरान हुए एफडीआई अंतर्प्रवाह के मुकाबले दोगुना है।

'विकसित भारत' के लिए राज्यों में सुधार : • राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न पड़ावों से जुडे सुधार के लिए 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 75, 000 करोड़ रुपए के प्रावधान का प्रस्ताव।

संशोधित अनुमान (आरई) 2023-24 : • उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों का संशोधित अनुमान 27.56 लाख करोड़ रुपए है जिसमें से कर प्राप्ति 23.24 लाख करोड़ रुपए है • कुल व्यय का संशोधित अनुमान 44.90 लाख रुपए है • 30.03 लाख करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति बजट अनुमान से अधिक रहने की उम्मीद है, जो अर्थव्यवस्था में मजबूत विकास दर और इसके औपचारीकरण को दर्शाता है • वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान 5.8 प्रतिशत हैं।

बजट अनुमान 2024-25 : • उधारी से इतर कुल प्राप्तियाँ और कुल व्यय क्रमश: 30.80 लाख करोड़ रुपए और 47.66 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। कर प्राप्तियाँ 26.02 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है • राज्यों

पटना नगर निगम द्वारा आयोजित संपत्ति कर हेतु स्व-कर निर्धारण संबंधित कार्यशाला में चैम्बर के पदाधिकारीगण एवं कार्यकारिणी के सदस्यगण शामिल हुए

इंटीग्रेटेड कमान्ड एण्ड कंट्रोल सेंदर में स्व-कर निर्धारण की जानकारी लेते चैम्बर के पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी के सदस्यगण

सम्पत्ति-कर हेतु स्व-कर निर्धारण कार्यशाला में उपस्थित माननीया महापौर, पटना श्रीमती सीता साहू, नगर आयुक्त श्री अनिमेष कुमार पराशर, भा.प्र.से., चैम्बर के पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी के सदस्यगण

कार्यशाला में उपस्थित चैम्बर के पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी के सदस्यगण

पटना नगर निगम की ओर से संपत्ति कर हेतु स्व-कर निर्धारण (Self Assessment) के संबंध में एक कार्यशाला का आयोजन दिनांक 19.2.2024 को पटना स्मार्ट सिटी बिल्डिंग सभागार में हुआ।

इस अवसर पर माननीया महापौर, पटना श्रीमती सीता साहु, नगर आयुक्त श्री अनिमेष कुमार पराशर, भा.प्र.से. उपस्थित थे। कार्यशाला में बिहार चैम्बर की ओर से महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन, पूर्व उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर एवं श्री मुकेश कुमार जैन, पूर्व महामंत्री श्री राजा बाबू गुप्ता, कार्यकारिणी सदस्य श्री राजेश जैन, श्री पवन भगत, श्री राकेश कुमार, श्री अजय कुमार, श्री बिनोद कुमार एवं श्री आशीष प्रसाद सम्मिलित हुए।

के पूंजीगत व्यय के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण योजना कुल 1.3 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ इस वर्ष भी जारी रखी जाएगी • वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान • वर्ष 2024-25 के दौरान डेटेड सिक्योरिटीज के जरिए सकल एवं शुद्ध बाजार उधारी क्रमशः 14.13 लाख करोड़ रुपए और 11.75 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान।

भाग - ख

प्रत्यक्ष कर : • वित्त मंत्री ने प्रत्यक्ष करों की मौजूदा दरों को बरकरार रखने का प्रस्ताव किया • पिछले 10 साल के दौरान प्रत्यक्ष कर संग्रह तिगुना, रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 2.4 गुना बढ़ी • सरकार करदाता सेवाओं में लाएगी सुधार • वित्त वर्ष 2009-10 तक की अवधि से जुड़ी 25 हजार रुपये तक की बकाया प्रत्यक्ष कर मांग को वापस लिया जाएगा • वित्त वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की 10 हजार रुपये तक की बकाया प्रत्यक्ष कर मांग को वापस लिया जाएगा • इससे एक करोड़ करदाताओं को होगा लाभ • सावरेन वेल्थ फंड अथवा पेंशन फंड द्वारा किए गए निवेश, स्टार्टअप के लिए कर लाभ 31.03.2025 तक बढाया गया • आईएफएससी इकाईयों की कुछ आय पर कर रियायत को एक साल बढ़ाकर 31.3.2024 से 31.3.2025 किया गया।

अप्रत्यक्ष कर : • वित्त मंत्री ने अप्रत्यक्ष करों और आयात शुल्कों की वर्तमान दरों को बकरार रखने का प्रस्ताव किया • जीएसटी ने देश में पूरी तरह बिखरी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एकीकृत किया • इस साल औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रह दोगुना होकर 1.66 लाख करोड़ रुपये हुआ • जीएसटी कर आधार दोगुना हुआ • राज्यों का राज्य जीएसटी राजस्व वृद्धि अनुपात (राज्यों को दी गई क्षतिपूर्ति सहित) जीएसटी से पहले की अवधि (2012-13 से 2015-16) के 0.72 से बढकर जीएसटी लागू होने के बाद की अवधि (2017-18 से 2022-23) के दौरान 1.22 हो गया • उद्योग जगत के 94 प्रतिशत उद्यमियों के अनुसार जीएसटी व्यवस्था काफी कुछ सकारात्मक रही है • जीएसटी से आपूर्ति श्रृंखला युक्तिसंगत बनी • जीएसटी से व्यापार और उद्योग पर अनुपालन बोझ कम हुआ • लॉजिस्टिक लागत और करों में कमी से वस्तु और सेवाओं के मूल्य घटने से उपभोक्ताओं को लाभ पहुँचा।

कोशी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों से मिले

कोशी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री अर्जुन दहलान एवं महासचिव श्री विवेक विशाल दिनांक 01 फरवरी, 2024 को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रांगण में पधारे एवं चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल एवं चैम्बर के पदाधिकारियों से मिले। कोशी चैम्बर के अध्यक्ष श्री अर्जुन दहलान ने बिहार चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल को अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर चैम्बर उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर एवं श्री प्रदीप चौरसिया, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, पूर्व उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एव कार्यकारिणी सदस्य श्री पवन भगत एवं श्री सुनील सराफ उपस्थित थे।

पिछले वर्षों के दौरान कर व्यवस्था को तर्कसंगत बनाने के प्रयास : • वित्त वर्ष 2013-14 में जहाँ 2.2 लाख रुपये तक की आय कर मुक्त थी, वहीं अब सात लाख रुपये तक की आय पर कोई कर देनदारी नहीं • खुदरा व्यवसायों के अनुमानित कराधान के लिए कारोबार सीमा को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये किया गया • पेशेवरों के लिए अनुमानित कराधान सीमा को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 75 लाख रुपये किया गया • वर्तमान घरेलू कंपनियों के लिए कॉरपोरेट आयकर दर 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत की गई • विनिर्माण क्षेत्र की नई कंपनियों के लिए कॉरपोरेट आयकर कर दर 15 प्रतिशत रखी गई

करदाता सेवाओं की उपलब्धियाँ : • कर रिटर्न प्रोसेस करने की औसत समय-सीमा 2013-14 के 93 दिन से घटकर दस दिन रह गई • बेहतर दक्षता के लिए चेहरा रहित आकलन और अपील की शुरूआत की गई • रिटर्न दाखिल करने के काम को सरल बनाने के लिए नया 26 एएस फार्म और पहले से भरे गये टैक्स रिटर्न विवरण के साथ इनकम टैक्स रिटर्न को अद्यतन किया गया • सीमा शुल्क सुधारों से आयतित माल छोड़ने के समय में आई कमी • अंतर्देशीय कंटेनर डिपो में यह 47 प्रतिशत घटकर 71 घंटे रह गया • एयर कार्गो परिसरों में यह 28 प्रतिशत घटकर 44 घंटे रह गया • समुद्री बंदरगाहों पर 27 प्रतिशत घटकर 85 घंटे रह गया

अर्थव्यवस्था - तब और अब : • वर्ष 2014 में अर्थव्यवस्था में सुधार और प्रशासन प्रणाली को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी थी। तब समय की जरूरत थी : • निवेश आकर्षित करना • बहुप्रतीक्षित सुधारों के लिए समर्थन जुटाना • लोगों में उम्मीद जगाना • सरकार 'राष्ट्र प्रथम' की मजबूत भावना के साथ सफल रही • "अब यह देखने का उचित समय है कि 2014 तक हम कहाँ थे और अब कहाँ हैं" वित्त मंत्री सरकार इस संबंध में सदन के पटल पर एक श्वेत-पत्र रखेगी। **(साभार) एनबी/एमजी/ पीआर/आरपी/हिंदी इकाई 26**

(Release ID: 2001202) Visitor Counter : 4962
Date : 01.02.2024

बिहार में रेलवे के लिए 10 हजार करोड़ मिले

यात्री ट्रेनों के परिचालन में सुधार लाने में भी मिलेगी मदद और ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी • बिहार के 92 स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चल रहा पुनर्निर्माण

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे बोर्ड से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बजट 2024-25 के रेल पर आधारित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार में रेलवे के लिए रिकॉर्ड 10, 032 करोड़ की धनराशि आवंटित की है। बिहार में रेलवे का 98 प्रतिशत विद्युतीकरण हो चुका है और 92 स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्निर्माण किया जा रहा है। बजट में भारतीय रेल के लिए तीन प्रमुख आर्थिक रेल गलियारा बनाने की घोषणा की गई है। इनमें ऊर्जा, खनिज एवं सीमेंट गलियारा, पोर्ट कनेक्टिविटी गलियारा एवं अधिक यातायात वाले गलियारा शामिल है। बहुविधि

पूर्व मध्य रेलवे को किस मद में कितना आवंटन

मद	राशि
दोहरीकरण	2719
नई लाइन	1268
आमान परिवर्तन	205
रेल पथ नवीकरण	1000
विद्युतीकरण	138
उपभोक्ता सुविधा	780
सड़क संरक्षा	503
सिगनल एवं दूरसंचार	265
यातायात सुविधा	244

(राशि करोड़ रुपये में)

मॉडलों वाली कनेक्टिविटी को संभव बनाने वे लिए प्रधानमंत्री गतिशक्ति के अंतर्गत इन परियोजनाओं की पहचान की गई है। इनसे रसद व्यवस्था संबंधी कार्यकुशलता बढ़ेगी और लागत में कमी आएगी। परिणामस्वरूप, अधिक यातायात वाले गलियारों में भीड़ कम होने से यात्री ट्रेनों के परिचालन में सुधार लाने में भी मदद मिलेगी और यात्री सुरक्षा एवं ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी। समर्पित मालभाड़ा गलियारों के साथ-साथ इन तीन इन तीन आर्थिक गलियारों से हमारी जीडीपी की विकास दर बढ़ेगी। साथ ही यात्रियों की सुविधा, आराम और सुरक्षा बढ़ाने के लिए 40 हजार सामान्य रेल डिब्बों की 'वंदे भारत' मानकों के अनुरूप बदलने की भी घोषणा की गयी है। इस बजट में पूर्व मध्य रेल के लिए 10 हजार 754 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 2.2.2024)**

दानापुर मंडल में 7 नई रेललाइन के लिए 2557 करोड़

326 करोड़ का प्रावधान है बिहटा-औरंगाबाद रेललाइन के लिए भी • माउंटेन मैन दशरथ मांझी का गाँव गहलोर भी रेल नेटवर्क से जुड़ेगा

दानापुर रेल मंडल की सात नई रेललाइनों के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। केन्द्र सरकार की ओर से पेश किए गए अंतरिम बजट में इन सात महत्वपूर्ण रेल लाइनों के लिए बड़ी धनराशि का प्रावधान किया है।

दानापुर रेल मंडल के एडीआरएम (परिचालन) आधार राज ने दिनांक 01.02.2024 को कार्यालय कक्ष में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इन सात नई रेल लाइनों के लिए 2557 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। अब बोधगया को भी रेल नेटवर्ट से जोड़ा जाएगा। साथ ही माउंटेन मैन दशरथ मांझी का गाँव गहलौर भी रेल नेटवर्क से जुड़ेगा। अंतरिम बजट में रेलवे की अवसंरचना पर भी जोर दिया गया है। ताकि नई ट्रेनों के चलाने की राह आसान हो सके। इससे वंदे भारत जैसी सेमी हाइस्पीड ट्रेनें अपनी पूरी क्षमता से पटिरयों पर दौड़ सकेंगी। बिहटा-औरंगाबाद रेललाइन के लिए बजट में 326 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। इस परियोजना के लिए हाल के महीनों में बड़ा आंदोलन हुआ था। 118 किमी

औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) के परियोजना समाशोधन (PCC) की बैठक में चैम्बर उपाध्यक्ष शामिल हुए

औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) के परियोजना समाशोधन समिति (PCC) की बैठक दिनांक 12 एवं 19 फरवरी, 2024 को श्री संदीप पौंडरिक, भा. प्र. से., अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, बिहार सरकार की अध्यक्षता में विभागीय सभाकक्ष में आयोजित हुई। इस बैठक में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर शामिल हुए।

लंबी रेल लाइन पर जमीनी स्तर पर काम शुरू हो जायेगा। इसके अलावा नटेसर-गया-बोधगया-चतरा नई रेल लाइन को 549 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। बोधगया के रेल नेटवर्क से जुड़ने से बौद्ध पर्यटकों को आने-जाने में सहुलियत होगी। वहीं 137 किमी की नई रेल लाइन नवादा से लक्ष्मीपुर तक बिछेगी। इसके लिए इस बार बजट में 620 करोड़ आवंटित हुए हैं। वजीरगंज से गहलोर होते हुए नटेसर तक 20 किमी की नई रेललाइन के लिए 320 करोड़ की धनराशि मिली है। झाझा से पटिया तक 20 किमी की नई लाइन के लिए 496 करोड़ का प्रावधान है। आठ किमी लंबी किउल में एक बाइपास लाइन बनेगी, जिसके लिए 128 करोड़ राशि आवंटित हुई है। सासाराम जाने के लिए आरा बाइपास लाइन के लिए 118 करोड़ आवंटित किए गए हैं। **(साभार : हिन्दुस्तान, 2.2.2024)**

राज्य के चहुँमुखी विकास पर जोर : चैम्बर

बजट में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना-प्रावैधिकी, पर्यटन उद्योग और निवेश को बढ़ावा, कृषि, ग्रामीण एवं शहरी आधार भूत संरचना का विकास और जन-कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर बल दिया गया

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने दिनांक 13.2.2024 को विधानसभा में पेश किये गये बिहार बजट 2024-2025 का स्वागत किया है। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इससे राज्य के चहुमुंखी विकास को बल मिलेगा।

चैम्बर के अध्यक्ष सुभाष पटवारी ने कहा कि बजट में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना-प्रावैधिकी, पर्यटन उद्योग एवं निवेश को बढ़ावा देने, कृषि, ग्रामीण एवं शहरी आधारभूत संरचना का विकास और जन-कल्यणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर बल दिया गया है। उन्होंने कहा कि बजट में पर्यटन और कृषि क्षेत्रों को बढ़ावा पर विशेष जोर दिये जाने का प्रतिकूल प्रभाव राज्य के आर्थिक विकास पर होगा। आईटी को बढ़ावा देने से रोजगार का सृजन होगा। बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों पर रियायत एवं सौर ऊर्जा को बढ़ावा सकारात्मक प्रभाव डालेगा और प्रदूषण पर बहुत हद तक नियंत्रण लगेगा। उन्होंने कहा कि उद्योग के लिए बजट में 1833 करोड़ 9 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। राज्य में औद्योगिकरण की रफ्तार तेज है और नए उद्योगों में निवेश आ रहे हैं। नए उद्योग चालू हो रहे हैं। ऐसे में 1833 करोड़ 9 लाख की राशि कम प्रतीत होती है। इसे और बढ़ाया जाना चाहिए। **(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 14.2.2024)**

बिहार बजट सरकार की प्राथमिकताएँ

1. **नियुक्ति और रोजगार :** वित्तीय वर्ष 2024-25 में 10 लाख से अधिक नियुक्ति के लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। इसमें पिछले सात माह दो लाख शिक्षकों को नियुक्ति हुई है। इसके अतिरिक्ति एक लाख शिक्षको की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। बिहार पुलिस में सिपाही के 21 हजार 391 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रगति पर है। वर्तमान में राज्य में एक लाख 10 हजार पुलिस बल है, इन्हें आगामी वर्षों में दो लाख 22 हजार करने का लक्ष्य रखा गया है। मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत 71 खिलाड़ियों को नौकरी दी गई।

2. **विभिन्न वर्गो का कल्याण :** आवासहीन एवं भूमिहीन परिवारों को एक लाख रुपये की सहायता जारी रहेगी। यूपीएससी और बीपीएससी प्रारभिक परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के साथ-साथ एसएससी, आइबीपीएस, आरआरबी की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण अत्यत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाएगी। मुस्लिम महिला तलाकशुदा को योजना के लाभ का दायरा बढ़ाया जाएगा। प्रत्येक जिले में कम-से-कम एक आवासीय विद्यालय का किया जाएगा निर्माण।

3. **स्वास्थ्य :** राज्य के 21 जिलों के सदर अस्पतालों को माडल बनाने का लक्ष्य इस साल पूरा कर लिया जाएगा। 580.09 करोड़ की लागत से सदर अस्पतालों को माडल बनाया जा रहा है। सात का निर्माण कार्य पूरा हो गया है, 14 का निर्माण कार्य पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य के विभिन्न अस्पतालों में पाँच हजार से अधिक बेड की सुविधा बढ़ जाएगी। 16 अनुमंडलीय अस्पताल के निर्माण के लिए 258.06 करोड़ रुपये उपलब्ध कराएँ गए हैं।

4. **शिक्षा :** दो लाख शिक्षकों की नियुक्ति से स्कूलों में पठन-पाठन की गुणवत्ता बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त राज्य में शिक्षकों की संख्या पाँच लाख का आकडा इस साल पार कर जाएगा। बालिका पोशाक, किशोरी स्वास्थ्य, छात्रवृत्ति, प्री मैट्रिक मुख्यमंत्री साइकिल योजना, मुख्यमंत्री बालक पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री मेधावृत्ति का दायरा बढ़ेगा। अब इंजीनियरिग छात्रों को 10 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

5. **महिला सशक्तीकरण :** जीविका सहित विविध महत्वाकांक्षी योजनाओं के माध्यम से महिला सशक्तीकरण को पंख देने का लक्ष्य रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में एक लाख तीन हजार नए समूहों का गठन किया जाएगा। इसका लाभ अब शहरी क्षेत्र की महिलाएँ भी उठा सकेंगी। इससे 20 लाख नए परिवारों को जोड़ा जाएगा। 52 लाख महिला किसानों को नई तकनीक से लैस किया जाएगा। स्वछांगिनी योजना से स्लम में की महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाएगा।

6. **कृषि एवं ग्रामीण विकास :** हर खेत तक सिंचाई का पानी कार्यक्रम के तहत विभिन्न जिलों, में कुल चयनित 1198 योजनाओं में 1173 योजनाओं को स्वीकृत किया गया है। इनसे से 621 योजनाएँ पूर्ण हो चुकी हैं। 552 का कार्य प्रगति पर है। किसानों के साथ गैर रैयत व महिला किसानों को बढ़ावा तथा छोटा किसान बड़ी खेती की अवधारणा बजट की नई बात है। छोटा किसान बड़ी खेती में संगठन बनाकर बीज से बाजार तक की व्यवस्था सुदृढ़ करने की बात है। चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023-28 के लिए एक लाख 62 हजार करोड़ रुपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है।

7. **उद्योग एवं उद्यमिता विकास :** लाजिस्टिक पालिसी 2023, राज्य में उद्योग लगाने का अनुकूल माहौल, प्लग एंड प्ले शेड की उपलब्धता, पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 18 व्यवसायों (बढई, नाव निर्माता, हथियार निर्माता, लोहार, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाला, सोनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची आदि) को करने के इच्छुक कारीगरों एवं शिल्पकारों को

बिहार कौशल विकास मिशन की शासी पर्षद की बैठक में चैम्बर उपाध्यक्ष सम्मिलित हुए

बिहार कौशल विकास मिशन की शासी पर्षद की 18वीं बैठक दिनांक 20 फरवरी 2024 को श्री विवेक कुमार सिंह, भा.प्र.से, विकास आयुक्त, बिहार की अधयक्षता में विभागीय सभाकक्ष में हुई। बैठक में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर सम्मिलित हुए।

प्रशिक्षाण व रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराना मुख्य लक्ष्य है। सरकार ने इन्हीं के सहारे औद्योगिक विकास की गति तेज करने की परिकल्पना की है।

8. पर्यावरण संरक्षण : राज्य के हरित आवरण को 17 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए वन से बाहर के क्षेत्रों में पौधारोपण तथा वन क्षेत्र में मिट्टी एवं जल सरक्षण कार्य किए जाएंगे। किसानों का भी कृषि वानिकी के लिए प्रेरित किया जाएगा। सभी प्रखंडों में निजी पौधशाला का विस्तार किया जाएगा। जहाँ से किसान आसानी से पौधे ले सकेंगे। सौर ऊर्जा के उपभोग को बढ़ाने के लिए जल जीवन हरियाली अभियान के अतर्गत सरकारी भवनों के साथ घरेलू उपभोक्ताओं को भी जोड़ा जाएगा। **(साभार : दैनिक जागरण, 14.2.2024)**

देश में सबसे अधिक रही बिहार की विकास दर

देश की आर्थिक वृद्धि दर 7.24 फीसदी, इसी अवधि में बिहार की अर्थव्यवस्था 10.64 फीसदी की रफ्तार से आगे बढ़ी

देश के विभिन्न राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के विकास दर की तुलना में बिहार में सर्वाधिक विकास दर दर्ज की गयी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के आकलन के अनुसार, वैश्विक स्तर पर आर्थिक वृद्धि दर वर्ष 2022-23 में 3.1 प्रतिशत रही जबकि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अंनुसार देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.24 प्रतिशत रही।

इसी अवधि में बिहार की अर्थव्यवस्था 10.64 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ काफी तेजी से बढ़ी है, जो बड़ी उपलब्धि है। बिहार के विकास दर के प्रथम स्थान पर रहने के बाद असम दूसरा प्रदेश है जहाँ विकास दर 10.2 प्रतिशत रही और तीसरे स्थान पर दिल्ली का स्थान है जहाँ 9.2 प्रतिशत विकास दर दर्ज की गयी है।

राज्य के लिए यह महत्वपूर्ण है कि पिछले एक दशक में सकल राज्य घेरलू उत्पाद के आकार में डेढ़ गुना से अधिक वृद्धि दर्ज की गयी है। आधार वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्य पर वर्ष 2012-13 के 2.57 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2022-23 में यह 4.42 लाख करोड़ रुपये हो गया है। औद्योगिक क्षेत्र में राज्य सरकार ने अनेक नीतिगत फैसले जैसे – विभिन्न प्रकार के औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, स्टार्टअप नीति इत्यादि का प्रभाव राज्य के निर्माण क्षेत्र में देखने को मिला है। इसका आकार वर्ष 2012-13 के 9,714 करोड़ से चार गुना बढ़कर वर्ष 2022-23 में 37,743 करोड़ हो गया है। परिवहन एवं संचार के क्षेत्र का आकार 30,372 करोड़ रुपये से बढ़कर 46,729 करोड़ रुपये हो गया है। यह वृद्धि दोगुनी से भी अधिक है। भंडारण में करीब चार गुनी वुद्धि दर्ज की गयी है, अर्थात यह 2012-2013 में 78 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 301 करोड़ हो गया है।

पशुपालन व मत्स्यपालन क्षेत्र में दोगुनी वृद्धि हुई : वर्ष 2012-13 में पशुपालन क्षेत्र का आकार 12,525 करोड़ रुपये था जो बढ़कर वर्ष 2022-23 में 28,621 करोड़ रुपये हो गया है। मत्स्य पालन क्षेत्र का आकार 3,768 करोड़ रुपये से बढ़कर 7,970 करोड़ रुपये हो गया है। इन दोनों क्षेत्रों में दोगुनी से अधिक वृद्धि दर्ज की गयी है।

गरीबी दर में गिरावट : नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में आर्थिक-सामाजिक क्षेत्रों में नीतिगत सुधार के फलस्वरुप वर्ष 2015-16 का बहुआयामी गरीबी सूचकांक 51.89 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2019-20 में 33.79 प्रतिशत हो गया है। गरीबी दर में गिरावट दर्ज करने वाले राज्यों में बिहार सर्वोपरि है। इस अवधि में जहाँ बिहार में गरीबी दर में 18.13 प्रतिशत अंकों की गिरावट दर्ज की गयी, वहीं पूरे देश में मात्र 9.89 प्रतिशत अंकों की ही गिरावट हुई। इस अवधि में राज्य के 2.25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं।

सामाजिक जरूरतों को भी प्राथमिकता

47 अंकों की गिरावट आई है मातृ मृत्यु दर में

राज्य में आर्थिक विकास के साथ-साथ सामाजिक विकास में भी कई उपलब्धियाँ हासिल की गयी है। इस बजट में शिक्षा एवं स्वास्थ्य के साथ अन्य सामाजिक जरूरतों को भी प्राथमिकता दी गयी है। मातृ मृत्यु अनुपात में सुधार महिलाओं के पोषण, स्वास्थ्य एवं सशक्तीकरण की स्थिति में सुधार का संकेत देता है। प्रतिदर्श निवंधन प्रणाली (एसआरएस) के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015-17 एवं 2018-20 के बीच मातृ मृत्यु दर में बिहार में 47 अंकों की गिरावट आयी है। वही, राष्ट्रीय स्तर पर यह गिरावट 25 अंक रही है। इस प्रकार, बिहार में मातृ मृत्यु दर की गिरावट की रफ्तार राष्ट्रीय औसत से बेहतर है, यह किसी भी राज्य के लिए बेहतर लोक सेवाओं का आईना है। संस्थागत प्रसव के मामले में जहाँ बिहार में 2005-06 से 2019-20 की अवधि में 56.3 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई है। वही, राष्ट्रीय स्तर पर 49.9 प्रतिशत अंको की वृद्धि हुई है। यह बिहार के उत्तम स्वास्थ्य संरचना को प्रदर्शित करता है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 14.2.2024)

स्टार्टअप यूनिटों को टैक्स छूट के लाभ से बिहार को भी फायदा

• बजट में स्टार्टअप कंपनियों के लिए तीन साल के कर छूट दिए गए • प्रदेश में सर्विस व उत्पादन में लगी सौ कंपनियों को होगा फायदा

केन्द्र के अंतरिम बजट में स्टार्टअप कंपनियों के लिए तीन साल के कर छूट का फायदा बिहार में सर्विस व उत्पादन में लगी लगभग एक सौ कंपनियों को होगा। यह लाभ 81-सी के तहत डिपार्टमेंट आफ प्रमोशन आफ इंडस्ट्री एण्ड इण्टरनल ट्रेड (डीपीआइआइटी) में निर्बंधित स्टार्टअप यूनिटों को मिलेगा।

अभी दो साल के लिए कर में छूट का था प्रविधान : वर्तमान में यह प्रविधान था कि कोई भी स्टार्टअप कंपनी अपने 10 साल के कामकाज में दो साल का कर छूट ले सकती थी। अंतिरम बजट में यह व्यवस्था की गई है कि अब 10 साल काम करने वाली कंपनी अपने किसी भी तीन साल के कामकाज में कर छूट का लाभ ले सकती है। छूट की व्यवस्था अगले वर्ष खत्म होने वाली थी पर इसे एक साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। इसका फायदा बिहार की स्टार्टअप यूनिटों से अधिक पश्चिम के राज्यों में बड़ी संख्या में आ रही स्टार्ट अप यूनिटों को विशेष रूप से मिलेगा। इसका फायद सभी स्टार्टअप कंपनियों को मिलेगा।

राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद की बैठक में चैम्बर उपाध्यक्ष शामिल हुए

राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद की 53वीं बैठक दिनांक 23 फरवरी 2024 को श्री विवेक कुमार सिंह भा. प्र. से. विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में बिहार विकास मिशन सभागार में आयोजित हुई।

इस बैठक में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर सम्मिलित हुए।

प्रदेश में उत्पादन से अधिक सर्विस सेक्टर में हैं स्टार्टअप कंपनियाँ: बिहार में स्टार्टअप यूनिटों की यह स्थिति है कि यहाँ वैसी यूनिटें अधिक हैं जो सर्विस सेक्टर में काम कर रहीं। उत्पादन के क्षेत्र में काम करने वाली यूनिट कम हैं। पर कर छूट का लाभ सभी श्रेणी के कंपनियों के लिए है।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 3.2.2024)

पेटीएम बैंक को 15 मार्च तक मोहलत

भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को सेवाएँ जारी रखने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। इसके तहत किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड उत्पाद, वॉलेट और फास्टैग में जमा या टॉप-अप स्वीकार न करने के आदेश की अंतिम तारीख 15 मार्च तक बढ़ा दी गई है। आरबीआई ने कहा कि व्यापारियों सहित ग्राहकों के हित को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।

रिजर्व बैंक ने 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक को ग्राहक खाते, प्रीपेड उत्पाद, वॉलेट व फास्टैग में 29 फरवरी के बाद जमा या टॉप-अप स्वीकार नहीं करने का निर्देश दिया था।

फास्टैग जारी करने वाली सूची से हटाया : भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की टोल संग्रहण इकाई भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड ने वाहन चालकों को परेशानी से बचने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अलावा 32 अधिकृत बैंकों से फास्टैग सेवाएँ लेने की सलाह दी। भारत में आठ करोड़ से अधिक फास्टैग उपयोगकर्ता हैं और पेटीएम पेमेंट्स बैंक की बाजार हिस्सेदारी करीब 30 प्रतिशत है।

पेटीएम ने मुख्य खाता एक्सिस बैंक में खोला : पेटीएम ब्रांड का संचालन करने वाली वन 97 कम्युनिकेशंस ने अपने मुख्य खाते को नियामकीय कार्रवाई में फंसे पेटीएम पेमेंट्स बैंक से एक्सिस बैंक में स्थानांतरित कर दिया है। नोडल खाता एक मास्टर खाते की तरह है जिसमें उसके सभी ग्राहकों, व्यापारियों के लेनदेन का निपटान किया जाता है। कंपनी ने दिनांक 16.2.2024 शाम को शेयर बाजार को इसकी सूचना दी।

आरबीआई ने अपने वायदे के मुताबिक पेटीएम पेमेंट्स बैंक से जुड़े 30 सवालों के जवाब भी दिनांक 16.2.2024 को जारी किया। यहाँ पर पेश हैं कुछ प्रमुख सवालों के जवाब-

- **क्या 15 मार्च के बाद भी पेटीएम बैंक खाते या वॉलेट से पैसे निकाल या जमा कर सकते हैं?** खाते या वॉलेट में उपलब्ध शेष राशि निकाली जा सकती है। इसे निकालने के लिए डेबिट कार्ड का उपयोग जारी रहेगा। राशि जमा नहीं होगी।
- **खाते या वॉलेट में ब्याज, रिफंड और कैशबैक प्राप्त होंगे?** हाँ, 15 मार्च के बाद भी खाते में रिफंड, कैशबैक, साझेदार बैंकों से स्वीप-इन या ब्याज जमा करने की अनुमति होगी। लेकिन वेतन या सरकारी सब्सिडी की राशि जमा नहीं होगी।
- **वॉलेट को बंद कर सकते हैं?** हाँ, इसे बंद किया जा सकता है। पूर्ण केवाईसी वॉलेट के मामले में शेष राशि को किसी अन्य बैंक में खाते में भेज पाएँगे।
- **पेटीएम बैंक द्वारा जारी फास्टैग या कॉमन मोबिलिटी कार्ड का उपयोग जारी रहेगी?** हाँ, उपलब्ध शेष राशि तक इनका उपयोग किया जा सकता है। 15 मार्च के बाद टॉप-अप या रिचार्ज की अनुमति नहीं होगी।

(साभार : हिन्दुस्तान, 17.2.2024)

आभूषणों को एक से दूसरी जगह ले जाने पर नहीं होगी मनाही, सीबीडीटी चुनाव सेल ने सर्राफा संगठनों की मांग पर उठाया कदम

आचार संहिता लागू होने पर गहने जब्त नहीं होंगे

आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान सोना, चांदी आदि धातुओं के कारोबारी परेशान नहीं होंगे। सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) के चुनाव सेल ने इस संबंध में एक पत्र जारी किया है। जिसमें चुनाव आचार संहिता के दौरान आने-जाने में सोना, चांदी के आभूषणों, बुलियन व अन्य मूल्यवान वस्तुओं को जब्ती सूची से बाहर रखा गया है।

ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन (एआईजेजीएफ) सहित अन्य सर्राफा संगठनों ने इस निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने बताया कि पहले आचार संहिता के दौरान सर्राफा कारोबारियों को जब्ती से काफी परेशानी होती थी। एक बार जब्ती-होने के बाद आभूषणों को छुड़ाने में छह महीने से ज्यादा का समय भी लग जाता था। अभी भी कई सर्राफा कारोबारियों का माल जब्ती में फंसा हुआ है। वे बताते हैं कि एक बार बहुमूल्य धातु जब्त होने पर कई विभागों की कार्रवाई और एनओसी प्राप्त करने में कारोबारियों को काफी परेशानी होती थी। नए नियम से कारोबारियों को काफी राहत मिलेगी।

ये मूल दस्तावेज रखना होगा जरूरी : • ज्वैलरी या बुलियन के मूल कर चालान • प्रमाणित स्टॉक सारांश • मालिक से प्राधिकार पत्र • वाहक की एक वैध फोटो आईडी • कारोबारी को धातु के साथ उसके दस्तावेज लेकर चलना होगा अनिवार्य • सीबीडीटी चुनाव सेल के निर्णय का सर्राफा संगठनों ने किया स्वागत

लंबे अर्से से है मांग : कई सर्राफा संगठन और ज्वेलरी उद्योग से जुडे कारोबारियों द्वारा चुनाव के समय आभूषणों की जब्ती से छूट की मांग केन्द्र से की जा रहा थी। पाटलिपुत्र सर्राफा संघ के अध्यक्ष बिनोद कुमार ने कहा कि कारोबारी संगठनों की इस व्यवहारिक मांग को लेकर केन्द्र सरकार की सीबीडीटी चुनाव सेल ने चुनाव आचार संहिता लगने के दौरान छूट दिया है।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 17.2.2024)

चार्ज, पेनाल्टी छिपाकर ब्याज दर में नहीं मिला सकेंगे बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रमुख नीतिगत दर यानी रेपो रेट को लगातार छठी बार 6.5% पर बरकरार रखा है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति की समीक्षा बैठक के बाद कहा कि वैश्विक अनिश्चितता और खुदरा महंगाई को 4%

से नीचे लाने की जरूरत को देखते हुए दर नहीं बदली गई। यानी होम-ऑटो लोन की ईएमआई न घटेगी, न बढ़ेगी।

हालांकि होम-ऑटो जैसे रिटेल और एमएसएमई लोन लेने वाले ग्राहकों को राहत मिली है। रिजर्व बैंक ने बैंक, एनबीएफसी और डिजिटल लोन एप कंपनियों के लिए 'की फैक्ट स्टेटमेंट (केएफएस)' अनिवार्य कर दिया है। इससे वे कोई चार्ज-पेनाल्टी नहीं छिपा सकेंगी। इसमें उन्हें बताना होगा कि लोन एग्रीमेंट की शर्तें क्या हैं। सालाना ब्याज दर (एपीआर) क्या रही। डॉक्यूमेंट चार्ज, प्रोसेसिंग फीस, पेनाल्टी कितनी ली। यह भी बताना होगा कि रिकवरी और शिकायत समाधान की प्रक्रिया क्या है। आरबीआई ने कहा, 'प्रोसेसिंग फीस, डॉक्यूमेंट चार्ज को भी सालाना ब्याज दरों में शामिल कर लिया गया है। ग्राहक को लोन की सही लागत के बारे में नहीं बताया जाता। इसलिए केएफएस अनिवार्य किया गया है।

रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स लगातार गैर अनुपालन कर रहा था। स्थिति सुधारने के लिए भी पर्याप्त समय दिया गया था। ऐसा नहीं हुआ, तब कदम उठाया गया।

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 9.2.2024)

बिहार के कुल कर्ज में हर साल 10% की वृद्धि

हर व्यक्ति पर 24 हजार रुपये से अधिक का कर्ज

राज्य सरकार अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए लगातार ऋण ले रही है। इस कारण बिहार के कुल कर्ज में हर साल करीब 10% की बढ़ोतरी हो रही है। बिहार का कुछ कर्ज जीडीपी का 38.6% तक पहुँच गया है। 2021-22 में राज्य पर कुल कर्ज बोझ 2,57,510 करोड़ था, जो 2022-23 में बढ़कर 2, 93, 596 करोड़ और 2023-24 में बढ़कर 3,19,618 करोड़ होने की संभावना है। चालू वित्तीय वर्ष के अंतिम तिमाही में भी राज्य सरकार करीब 23 हजार करोड़ ऋण लेगी। चालू वित्तीय वर्ष में बिहार में प्रति व्यक्ति करीब 24, 583 रुपये कर्ज होने की संभावना है।

पड़ोसी राज्यों पर कर्ज का बोझ

राज्य	2022	2023	2024
बिहार	2,57,634	2,93,850	3,19,618
झारखण्ड	1,13,568	1,18,855	1,31,455
उत्तर प्रदेश	6,46,321	6,93,577	7,69,245
प. बंगाल	5,48,255	5,96,725	6,58,428

(राशि करोड़ में)

वित्तीय वर्ष 2023-24 में सूद के लिए 18354 करोड़ का प्रावधान : बढ़ते कर्ज के कारण हर साल बिहार को सूद के रूप में बड़ी राशि चुकानी पड़ रही है। 2022-23 के बजट में कर्ज का सूद चुकाने के लिए 16,305 करोड़ का प्रावधान किया गया था। जो चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में सूद के मद का प्रावधान बढ़कर 18,354 करोड़ हो गया है। यानी एक साल के अंदर ही सूद के मद में 2049 करोड़ की वृद्धि हुई है। **(साभार : प्रभात खबर, 9.2.2024)**

कर माफी में एक लाख रुपये तक राहत संभव

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने कहा है कि अंतरिम बजट में 25,000 रुपये तक की बकाया कर मांग को वापस लेने की घोषणा के तहत करदाताओं को एक लाख रुपये तक की राहत मिल सकती है। इससे उन करदाताओं को लाभ होगा, जिन्हें निर्धारित अवधि में एक साल से अधिक के लिए कर मांग को लेकर नोटिस मिले हैं। इस कदम से लगभग 80 लाख करदाताओं को लाभ होगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के लिए अपने अंतरिम बजट भाषण में वित्त वर्ष 2009-10 तक 25,000 रुपये और वित्त वर्ष 201-11 से 2014-15 तक 10,000 रुपये तक की बकाया प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस लेने की घोषणा की। यानी इस अवधि के लंबित मामलों में आयकर देनदारी माफ कर दी जाएगी।

राहत देना मकसद : गुप्ता ने कहा कि इस पहल का मकसद करदाताओं को राहत देना है। इसके तहत हम प्रति करदाता एक लाख रुपये तक की सीमा रखने का प्रयास करेंगे। यानी करदाता को अगर एक साल से अधिक के लिए कर मांग को लेकर नोटिस मिला है तो उसे एक लाख रुपये तक की राहत मिल सकती है। हम इस बारे में जरूरी आदेश जारी करेंगे।

8.5 करोड़ रिटर्न दाखिल : प्रत्यक्ष कर (आयकर और कंपनी कर) संग्रह के बारे में उन्होंने कहा कि 31 जनवरी तक रिफंड वापसी के बाद 14.46 लाख करोड़ रुपये आये है। जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 20 प्रतिशत ज्यादा है। और अगर रिटर्न की बात की जाए तो कुल मिलकर 8.5 रिटर्न दाखिल किए गए हैं। जिसमें से लगभग 8.2 करोड़ वित्त वर्ष 2023-24 के लिए है।

12 हजार खाली पदों को भरा जाएगा : नितिन गुप्ता ने यह भी बताया कि आयकर विभाग में 10,000 से 12,000 तक कर्मचारियों की कमी है और खाली पड़े पदों पर नियुक्ति के लिए कदम उठाए जा रहे है। ये पद मुख्य रूप से ग्रुप सी श्रेणी के हैं। **(साभार : हिन्दुस्तान, 5.2.2024)**

राज्य में मार्च तक स्थापित होंगे वर्चुअल राजस्व कोर्ट

सीओ और डीसीएलआर स्तर पर संचालित कोर्ट में ऑनलाइन सुनवाई भी होगी।

राज्य में अब सीओ और डीसीएलआर से जुड़े कोर्ट में ऑनलाइन माध्यम से सुनवाई की व्यवस्था शुरू होने जा रही है। सभी राजस्व कोर्ट में मामलों की सुनवाई ऑनलाइन माध्यम से भी हो सकेगी। इस नई सुविधा की शुरुआत इस वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह से शुरू होने की संभावना है।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इससे जुड़ी सभी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। यह सुविधा सभी 101 अनुमंडल स्तरीय डीसीएलआर (भूमि राजस्व अपर समाहर्ता) और 534 अंचल स्तरीय सीओ (अंचलाधिकारी) कार्यालय में एक साथ शुरू होगी। इसके तहत कोई भी व्यक्ति अगर जमीन से जुड़े अपने किसी मामले को लेकर डीसीएलआर या सीओ कोर्ट में अपनी निर्धारित तारीख में उपस्थित नहीं हो पाते हैं, तो वे भेजे गए लिंक पर क्लिक करके सीधे जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से ही कोर्ट की पूरी प्रक्रिया में शामिल होकर कार्यवाही का हिस्सा बन सकते हैं।

यह होगी सुविधा : जमीन से जुड़ी तारीखें सिर्फ लोगों की अनुपस्थिति की वजह से आगे नहीं बढ़ेगी। इससे मामले की सुनवाई समय पर हो सकेगी। जमीन विवाद के मामले के निपटारे में तेजी आएगी। लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक तरफा फैसला सुनाने जैसी शिकायत नहीं होगी।

"वर्चुअल राजस्व कोर्ट की सुविधा मार्च अंत तक शुरू हो जाने की संभावना है। इसकी तैयारी अंतिम चरण में है। कोई व्यक्ति किसी कारण से फिजिकल उपस्थित नहीं हो सकते तो वे इस वर्चुअल माध्यम से कही से जुड़ सकते हैं।" **– जय सिंह,** सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 8.2.2024)

नियमों से संतुष्ट न होने पर अब 30 दिनों तक वापस कर सकेंगें पालिसी

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) ने कंपनी की नियम और शर्तों से संतुष्ट नहीं होन पर पालिसी को वापस करने की अवधि (फ्री लुक पीरियड) को 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन करने का प्रस्ताव दिया है। साथ ही नियामक ने जीवन बीमा पालिसियों के लिए नामिनी को अनिवार्य बनाने को भी कहा है।

मौजूदा समय में कोई भी बीमाधारक नियमों और शर्तों से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में पालिसी दस्तावेज मिलने की तारीख से 15 दिनों की 'फ्री लुक' अवधि के भीतर उससे अलग हो सकता है। हालांकि अगर पालिसी आनलाइन खरीदी गई है तो यह अवधि 30 दिन है। नियामक ने इन प्रस्तावों पर चार मार्च तक राय मांगी है। मसौदा प्रस्ताव के मुताबिक, पालिसी रिफंड के इलेक्ट्रानिक हस्तांतरण और बीमा दावों के भुगतान को सक्षम बनाने के लिए

बीमा कंपनी को प्रस्ताव चरण में ही बीमाधारक के बैंक खातों का विवरण एकत्र करना चाहिए।

इंश्योरेंस सहूलियत के लिए बीमा सुगम ला रहा है इरडा : इंश्योरेंस खरीदने वालों से लेकर बेचने वालों तक की सहूलियत के लिए इरडा बीमा सुगम नामक इंश्योरेंस इलेक्ट्रानिक मार्केटप्लेस ला रहा है। इस प्लेटफार्म में सभी प्रकार की इंश्योरेंस बेचने वाली कंपनी, इंटरमीडिएरीज और ग्राहक होंगे। जहाँ उपभोक्ता अपनी सुविधा के मुताबिक इंश्योरेंस की खरीदारी कर सकेंगे। सभी इंश्योरेस की जानकारी उनके सामने होगी। **(साभार : दैनिक जागरण, 15.2.2024)**

अब श्रीलंका और मॉरीशस में भी चलेगा 'भारत का सिक्का'

01 जनवरी 2020 से यूपीआई ट्राजैक्शन के लिए एक जीरो-चार्ज फ्रेमवर्क हुआ मैडेटरी • 2 फरवरी 2024 को फ्रांस में इंडियन एम्बेसी ने पेरिस के एफिल टावर पर लॉन्च किया यूपीआई

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 12.2.2024 को श्रीलंका और मॉरीशस में यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सर्विस लॉन्च कर दिया है। श्रीलंका और मॉरीशस जाने वाले भारतीय नागरिकों के साथ-साथ भारत की यात्रा करने वाले मॉरीशस के नागरिक इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। हाल ही फ्रांस में भी यूपीआई सर्विस की शुरूआत हुई थी, बता दें, लॉन्च के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत का यूपीआई अब एक नई जिम्मेदारी निभा रहा है, यूनाइटिंग पार्टनर्स विद इंडिया। वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए हुए कार्यक्रम में मोदी के साथ श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनौथ के साथ तीनों देशों के सेंट्रल बैंक के गवर्नर भी मौजूद थे।

फ्रांस-सिंगापुर समेत कई देशों में एक्टिव : श्रीलंका और मॉरिशस में होने वाली यूपीआई लॉन्चिग से पहले भारतीय पेमेंट सिस्टम फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, नेपाल, भूटान एक्टिव है। बता दे कि यूपीआई के आने के बाद से ऑन-लाइन ट्रांजैक्शंस में खासी तेजी देखने को मिली है। इसमें साल दर साल इजाफा हो रहा है और इसका अंदाजा एनपीसीआई के आंकड़ों को देखकर लगाया जा सकता है। इसके मुताबिक, बीते साल दिसम्बर 2023 में भी यूपीआई से 18.23 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड का लेन-देन किया गया था। जो कि इससे पिछले साल 2022 की समान अवधि की तुलना से 54 फीसदी आधिक था।

"आज का दिन तीन मित्र देशों के लिए सपेशल है। हम अपने ऐतिहासिक संबंधों को मॉडर्न डिजिटल तरीके से जोड़ रहे है। फिनटेक के जरिए कनेक्टिविटी से ट्रांजेक्शन ही नहीं बल्कि कनेक्शन भी बनेंगे। भारत का यूपीआई अब तक नई जिम्मेदारी निभा रही है। यूनाइटिंग पार्टनर्स विद इंडिया।"

– नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री, भारत

(विस्तृत : आइनेक्स्ट, 13.2.2024)

इनएक्टिव बैंक अकाउंट चालू रखने के हैं यह चार फाइनेंशियल नुकसान

बैंक में अकाउंट खुलवाना आजकल बहुत आसान हो गया है। खुलवाने की कोई लिमिट भी नहीं है। यही वजह है कि आजकल बहुत से लोगों के एक से ज्यादा बैंक अकाउंट हैं। इनमें से कुछ अकाउंट्स का टाइम के साथ इस्तेमाल न के बराबर हो जाता है। अगर आपका भी कोई ऐसा बैंक अकाउंट है जिसका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उसे तुरत बंद कराएँ। ऐसा न कराने पर न केवल आपको फाइनेंशियल नुकसान होगा, बल्कि आप किसी बड़ी मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। एक सच्चाई यह भी है कि ज्यादातर लोग यूज नहीं हो रहे बैंक अकाउंट को बंद नहीं कराते। उनको लगता है कि अकाउंट अगर चालू है तो उन्हें कोई नुकसान नहीं हो रहा है। हालांकि, उनका ऐसा मानना बिल्कुल भी सही नहीं है। आज हम आपको इनएक्टिव अकाउंट्स को बंद न काराने से होने वाले नुकसान के बारे में समझाते हुए उसे बंद करने का प्रोसेस भी बताएंगे।

1. **मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना करने पर चार्ज** • 2. **देने पड़ते है डेबिट कार्ड चार्जेज** • **ITR भरते वक्त भी है समस्या** • 4. **अकाऊँट का हो सकता है गलत इम्तेमाल**

बैंक अकाउंट कैसे बंद करें? : • आप जिस बैंक अकाउंट को बंद करना चाहते है, उसकी बैंक शाखा में जाएँ • बैंक के पास उपलब्ध अकाउंट बंद करने का फॉर्म भरे • दूसरे बैंक अकाउंट का डाटा दें। जिसमें आप अपने इनएक्टिव अकाउट के बचे हुए पैसे भेजना चाहते है • अगर जरूरी हो, तो डी-लिकिंग अकाउंट फॉर्म भरें • अनयूज्ड चेक बुक और डेबिट कार्ड जमा करें • अकाउट बंद करने के शुल्क का भुगतान करें। अगर शुल्क लगा है तो।

पहले से पता कर लेने चाहिए चार्जेस : बैंक अकाउंट बंद करने से पहले व्यक्ति को उस क्रेडिट कार्ड भुगतान, ट्रेडिंग अकाउंट और आवर्त्ती जमा आदि से डी-लिंक करना चाहिए। अगर बैक अकाउट खोलने के 14 दिनों के अंदर बंद किया जाता है, तो आम तौर पर बैंक अकाउंट बंद करने का फीस नहीं लेती है। वही, अकाउंट बंद करने का फीस खोलने की तारीख से 14 दिनों और 1 साल के बीच बंद किए गए बैंक खातों पर लगाया जाता है, जबकि 1 साल पूरा होने के बाद अकाउंट बंद कराने पर बैंक चार्ज ले भी सकते है या नहीं भी अकाउट बंद करने का चार्ज हर बैंक में अलग-अलग हो सकता है।

(विस्तृत : आईनेक्स्ट, 13.2.2024)

राज्य के 25 उत्पादों को मिली स्वीकृति

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआइ) ने केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (पीएमएफएमइ) स्कीम के तहत बिहार सहित 35 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के 713 जिलों के लिए एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) को स्वीकृति दे दी है। बिहार में 38 जिलों के लिए 25 उत्पादों को स्वीकृति मिली है। इनमें मखाना, बेचन-सत्तू, मिठाई, लीची, मिर्च, जर्हालु आम, तिल से बने उत्पाद, पपीता, कटहल, चावल, केला, स्ट्रोबेरी, अनन्नास, आलू, पान, बेकरी, मक्कर, हल्दी, टमाटर, प्याज, पुदीना, शहर और गन्ना आधारित उत्पाद शामिल हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में इस योजना को लागू किया गया है।

एक जिला, एक उत्पाद की यह है सूची

जिले	उत्पाद
अररिया	मखाना
अरवल	दाल आधारित (बेसन/सत्तू)
औरंगाबाद	स्ट्रोबरी
बांका	कतरनी चावल आधारित उत्पाद
बेगूसराय	मिर्च
भागलपुर	जर्दालू आम
भोजपुर	पारंपरिक मिठाइया और मिष्ठान (खुरमा और बेलग्रामी)
बक्सर	पारंपरिक मिठाइयाँ (पापड़ी)
दरभंगा	मखाना
पूर्वी चंपारण	लीची
गया	तिल आधारित उत्पाद
गोपालगंज	पपीता
जमुई	लघु वन उत्पाद (कटहल)
जहानाबाद	दाल आधारित (बेसन/सत्तू)
कैमूर	चावल आधारित उत्पाद (पोहा,मुरमुरा आदि)
कटिहार	मखाना
खगड़िया	केला
किशनगंज	अनन्नास
लखीसराय	टमाटर
मधेपुरा	आम
मधुबनी	मखाना
मुंगेर	चावल आधारित
मुजफ्फरपुर	लीची
नालंदा	आलू
नवादा	पान की बेल

पटना	बेकरी उत्पाद
पूर्णिया	मक्का आधारित उत्पाद
रोहतास	चावल आधारित उत्पाद
सहरसा	मखाना
समस्तीपुर	हल्दी
सारण	टमाटर
शेखपुरा	प्याज
शिवहर	केले आधारित उत्पाद
सीतामड़ी	लीची
सीवान	पुदीना
सुपौल	मखाना
वैशाली	शहद
पश्चिम चंपारण	गन्ना आधारित उत्पाद

(साभार : प्रभात खबर, 9.2.2024)

भारत की वर्तमान सौर क्षमता

73318.49 मेगावाट हे भारत की मौजूटा कुल सौर ऊर्जा क्षमता (31 दिसम्बर, 2023 तक) जिसमें 56920.20 मेगावाट की ग्राउंड माउंटेड सौर संयंत्र क्षमता • 111078.95 मेगांवाट ग्रीड कनेक्टेड रूफ टॉप सौर क्षमता • 2571.96 मेगावाट की हाइब्रेड परियोजनाए! (सोलर घटक) • 2748.39 मेगावाट की ऑफ ग्रीड सौर क्षमता शामिल है।

कुल सौर ऊर्जा क्षमता में राजस्थान शीर्ष पर : नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार, कुल सौर क्षमता के मामले में राजस्थान 18777.14 मेगावाट के साथ देश में शीर्ष पर और गुजरात दूसरे स्थान पर है। छत पर स्थापित सोलर प्रणाली क्षमता के संदर्भ में जहाँ गुजरात 2898.16 मेगावाट के साथ सूची में सबसे ऊपर है, वहीं1716.30 मेगावाट के साथ महाराष्ट्र दूसरे और 1562.11 मेगावाट के साथ कर्नाटक तीसरे स्थान पर है।

अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन : भारत सरकार विशेष रूप से विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में एनर्जी ट्रांजिशन में मदद करने के लिए वित्त वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के लिए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन को प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान कर रही है।

कुल सौर क्षमता वाले शीर्ष राज्य (मेगावाट में)

राज्य	सौर ऊर्जा क्षमता	राज्य	सौर ऊर्जा क्षमता
राजस्थान	18777.14	महाराष्ट्र	5080.28
गुजरात	10349.07	तेलंगाना	4712.98
कर्नाटक	9412.71	आंध्र प्रदेश	4565.60
तमिलनाडु	7360.94	मध्य प्रदेश	3170.05

(स्रोत : नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार)

(साभार : प्रभात खबर, 6.2.2024)

मकान में जितने बिजली कनेक्शन होंगे, उसी आधार पर अब लगेगा संपत्ति कर

मकानों व किसी भी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का अब नए सिरे से संपत्ति कर का निर्धारण होगा। लोगों को अब उनके मकानों, दुकानों व कॉमर्शियल कांप्लेक्स में बिजली कनेक्शन की संख्या के आधार पर भी संपत्ति कर देने होंगे। कुल मिलाकर संपत्ति कर का दायरा बढ़ाया जाएगा। जिसके चलते वर्तमान की तुलना में लोगों को संपत्ति कर अथवा होल्डिंग टैक्स का भार बढ़ जाएगा। पटना समेत राज्यभर के सभी नगर निकायों में संपत्ति कर के दायरे में अधिक से अधिक लोगों को लाने के लिए सरकार के स्तर पर नए सिरे से कवायद शुरू कर दी गई है। इसके लिए शहर में बिजली कनेक्शन की संख्या के आधार पर सर्वे शुरू किया जाएगा। नगर विकास एवं आवास विभाग ने राज्य की बिजली कंपनी से शहरों में दिए गए बिजली कनेक्शन का आंकड़ा मांगा है। पहले चरण में पटना नगर निगम अपने क्षेत्र के मकानों व कॉमर्शियल प्रतिष्ठानों की जानकारी बिजली कनेक्शन के जरिए जुटाएगा। इस सर्वे के सफल होने के बाद इस व्यवस्था को राज्य के सभी 161 नगर निकायों में भी लागू किया जाएगा।

"राज्य संपत्ति कर के दायरे को बढ़ाने के लिए सर्वे होगा। शहरों में बिजली कनेक्शन की संख्या को आधार बना सर्वे होगा। पटना नगर निगम से शुरूआत होगी। इसके बाद राज्यभर में इसी व्यवस्था से सर्वे होगा, ताकि नगर निकायों में संपत्ति कर के दायरे को बढ़ाया जा सके।"

– संतोष कुमार मल्ल, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 7.2.2024)

फ्री बिजली स्कीम में ऐसे करें अप्लाई

देश के 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली देने के लिए केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा पीएम सूर्यघर योजना लॉन्च की है। इसके तरहत हर महीने 300 यूनिट बिजली बिल्कुल फ्री मिलेगा। इस योजना पर केन्द्र सरकार 75,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश करेगी। अगर आपको भी इस स्कीम का लाभ लेना है, तो जल्द अप्लाई कर दें।

पीएम फ्री बिजली स्कीम के तहत आवेदन करना बेहद ही आसान है। इसके लिए आपको महज 5 मिनट का समय निकालना होगा खास बात ये है कि इस योजना के तहत 300 यूनिट फ्री बिजली के साथ ही सरकार सब्सिडी का लाभ भी दे रही है, जो सीधे आपके बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस स्कीम को सतत विकास और लोगों की भलाई वाली योजना बताया था।

अगर आप अपने घर में 2 केवी का रूफटॉप सोलर लगवाना चाहते हैं, तो वेबसाइट पर मौजूद कैलकुलेटर के हिसाब से इसके लिए कुल प्रोजेक्ट कॉस्ट 47000 रुपये होगा। जिसपर सरकार की ओर से 18000 रुपये सब्सिडी मिलेगी। इस तरह से ग्राहक को रूफटॉप सोलर लगवाने के लिए 29000 रुपये का भुगतान करना होगा। नियम के मुताबिक इसके लिए 130 वर्ग फीट की जगह होना चाहिए। 47000 रुपये की लागत से तैयार सोलर प्लांट से हर रोज 4.32 के डब्ल्यूएच / प्रत्येक दिन बिजली पैदा होगी, जो सालाना 1576 के केडब्ल्यूएच / प्रत्येक साल बैठती है। इससे ग्राहक को रोजाना 12.96 रुपये की बचत होगी, और सालभर 4730 रुपये की बचत होगी।

वहीं अगर आपका रूफटॉप एरिया 700 स्कॉयर फीट है तो फिर 3 किलोवाट के पैनल के लिए आपका इन्वेस्टमेंट 80,000 रुपये होगा और इसमें आपको मिलने वाली सब्सिडी 36,000 रुपये होगी। यानी आपकी इसके लिए जेब से सिर्फ 50, 000 रुपये खर्च करने होंगे। **(साभार : आज, 16.2.2024)**

सूबे में 40 एक्सक्लूसिव इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पंप खुलेंगे

सूबे में 40 से अधिक एक्सक्लूसिव इथेनॉल मिक्स पेट्रोल पंप खुलेगा। इन पेट्रोल पंप पर केवल 20 फीसदी मिक्स इथेनॉल वाला पेट्रोल मिलेगा। बिहार में यह पंप दूसरे चरण में खुलेगा। जबकि पहले चरण में यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक में ऐसे 400 पेट्रोल पंप अगले छह-आठ माह में शुरू हो जायेंगे। इसके लिए तैयारी शुरू हो गयी है। दरअसल, इ 20 इथेनॉल उपेयोग से पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम होने के साथ पर्यावरण संरक्षण भी होगा।

फिलवक्त सूबे में इंडियन ऑयल कारपोरेशन के इ 20 इथेनॉल पेट्रोल पंपों की संख्या 236 और बीपीसी के पास इ-20 के 20 पेट्रोल पंप हैं। इन्हीं में से प्राथमिकता और मांग के अनुसार 40 एक्सक्लूसिव इथेनॉल मिक्स पेट्रोल पंप खुलेंगे, इस वक्त इथेनॉल मिक्स पेट्रोल की मांग बिहार के ग्रामीण इलाके में है।

ट्रायल के तौर पर हो रही बिक्री : बिहार पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रभात कुमार सिंह ने बताया कि इस वक्त सूबे के लगभग 600 पेट्रोल पप पर इ-20 इथेनॉल मिक्स पेट्रोल की बिक्री ट्रायल के तौर पर हो रही है। एचपीसी के दो प्लांट लौरिया और सुगौली में हैं जहाँ इथेनॉल का उत्पादन हो रहा है। **(विस्तृत : प्रभात खबर, 10.2.2024)**

बिहार सरकार
उद्योग विभाग
बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति, 2023

उद्देश्य: राज्य में ग्रीन फिल्ड न्यू 100 प्रतिशत स्टैन्डअलोन (Stand alone) इथेनॉल एवं कम्प्रेस्ड बायो गैस (CBG)/ बायो सी. एन. जी. उत्पादन इकाइयों का सर्वांगीण विकास।

पूंजीगत अनुदान :

संयंत्र एवं मशीनरी लागत का 15 प्रतिशत, अधिकतम पाँच करोड़ रुपये

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ

- स्टाम्प शुल्क/ पंजीकरण शुल्क की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति।
- भूमि सम्परिवर्तन शुल्क की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति।
- बैंकों के लिए गए कर्ज पर 10 प्रतिशत की ब्याज प्रतिपूर्ति, अधिकत्तम 20 करोड़ रुपये।
- 5 वर्ष अवधि के लिए कैप्टिव पावर सहित विद्युत शुल्क की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति।
- 5 वर्ष अवधि के लिए SGST की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति।
- कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए प्रति कर्मचारी 20 हजार रुपये का अनुदान।
- कमचारियों के ESI और EPF योगदान पर 5 साल के लिए रोजगार लागत सब्सिडी (पुरूष कर्मचारी 50 प्रतिशत, महिला कर्मचारी 100 प्रतिशत)

सम्पर्क करें : sipb.care@bihar.gov.in/industries
www.statebihar.gov.in / industries • Toll Free No. : 18003456214

(साभार : दैनिक भास्कर, 7.2.2024)

36 अरब से बनेंगे 20 लाख टन के अनाज भंडार

चौथे कृषि रोडमैप के तहत बिहार में 20 लाख टन क्षमता का अन्न भंडार गृह का निर्माण प्रस्तावित है। अगले पाँच वर्ष 2028 तक इसका निर्माण होगा। 36 अरब 51 करोड़ 20 लाख रुपये निर्माण कार्य पर खर्च करने का प्रस्ताव है। इन पाँच वर्षों में प्रस्तावित राशि 2 अरब 76 करोड़ चार लाख रुपये बढ़ जायेगी। वर्ष 2023-24 में यहाँ एक लाख टन क्षमता का अन्न भंडार गृह निर्माण पर एक अरब 44 करोड़ 80 लाख रुपया खर्च होना है। वहीं, वर्ष 2028 में एक लाख टन क्षमता का ही अन्न भंडार गृह निर्माण पर दो अरब 12 करोड़ की राशि खर्च होगी। इन पाँच वर्षों में एक लाख टन क्षमता का अन्न भंडार गृह निर्माण पर 19 करोड़ 28 लाख रुपये की राशि बढ़ जायेगी। पहले वर्ष दो और इसके अगले दो वर्षों में चार-चार तथा इसके बाद के दो वर्षों में पाँच-पाँच लाख टन क्षमता का अन्न भंडार गृह निर्माण प्रस्तावित है। अन्न भंडार गृह का निर्माण हो जाने से राज्य के किसानों को होगी सहूलियत।

पहले वर्ष 14 करोड़ की राशि बढ़ायी गयी : वर्ष 2023-24 में एक लाख टन अन्न भंडार गृह निर्माण की लागत एक अरब 44 करोड़ 80 लाख रुपये निर्धारित की गयी है। इसके ठीक अगले वर्ष 2024-25 में एक लाख टन क्षमता की प्रस्तावित राशि 1 अरब 59 करोड़ 28 लाख निर्धारित की गयी है। एक वर्ष के बाद ही 14 करोड़ 48 लाख रुपये का इजाफा किया गया है। इसके अगले वर्ष 2025-26 में एक लाख टन की राशि 1 अरब 75 करोड़ 20 लाख 80 हजार निर्धारित है। इस वर्ष 15 करोड़ 92 लाख रुपये की वृद्धि कर दी गयी है।

पाँच वर्ष 19 करोड़ रुपये का इजाफा : वर्ष 2026-27 में 1 अरब 92 करोड़ 72 लाख प्रति एक लाख टन क्षमता के अन्न भंडार पर खर्च होंगे। इस वर्ष 17 करोड़ 52 लाख रुपये का इजाफा किया गया है। वर्ष 2027-28 में प्रति एक लाख टन अन्न भंडार गृह के निमाण पर 2 अरब 12 करोड़ रुपये निर्धारित है। बीते वर्ष से इस साल 19 करोड़ 28 लाख रुपये निर्धारित हैं। बीते वर्ष से इस साल 19 करोड़ 28 लाख रुपये की वृद्धि की गयी है।

(विस्तृत : प्रभात खबर, 15.2.2024)

अब गंगा के रास्ते बांग्लादेश तक भेजी जाएगी शाही लीची

गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की तरक्की में वहाँ के बंदरगाहों की बड़ी भूमिका है जिनके माध्यम से दुनिया भर से माल ढुलाई का काम होता है। ये राज्य समुद्र के किनारे स्थित है इसलिए यहाँ इंटरनेशलल पोर्ट है। बिहार एक लैंड लॉक्ड स्टेट है इसलिए यहाँ किसी बंदरगाह की संभावना नहीं थी। लेकिन अब यह हकीकत में बदल गई। पटना से सटे सारण जिले के कालूघाट में बिहार के अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन हो गया। इसका उद्घाटन यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज व आयुष, सर्बानंद सोनोवाल ने बटन दबा कर किया। **(विस्तृत : आईनेक्स्ट, 16.2.2024)**

Statement about ownership and other particulars about newspaper of the Bihar Chamber of Commerce & Industries monthly Bulletin to be published in the first issue every year after last day of February.

Form - IV
(See Rule -8)

1.	Place of Publication	Bihar Chamber of Commerce & Industries, Khem Chand Chaudhary Marg, Patna-800 001
2.	Periodicity of its publication	Monthly
3.	Printer's Name Whether Citizen of India? (If foreigner, state the Country of origin) Address	A. K. Dubey Indian Deputy Secretary Bihar Chamber of Commerce & Industries, Khem Chand Chaudhary Marg, Patna-800001
4.	Publisher's Name Whether Citizen of India? (if foreigner, State the Country of Origin) Addrss	A. K. Dubey Indian Deputy Secretary Bihar Chamber of Commerce & Industries, Khem Chand Chaudhary Marg, Patna-800001
5.	Editor's Name Whether Citizen of India? (If Foreigner, State the Country of Origin) Address	Shri Pashupati Nath Pandey Indian M/s Jugeshwar Pandey New Lalji Tola Patna - 800001
6.	Name and Address of Individual who own the newspaper and partners of Share-holders	Bihar Chamber of Commerce & Industries Khem Chand Chaudhary Marg Patna-800 001

I, A. K. Dubey, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

A. K. Dubey
Publisher

EDITORIAL BOARD

Editor
PASHUPATI NATH PANDEY
Secretary General

Convenor
SUBODH KUMAR JAIN
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 0612-2677605, 2677505, 2677635
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Designed & Printed by : Sharada Enterprises, Ph. : 0612-2667296